



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2014/श्रावण 20, 1936

No. 198]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2014/SRAVANA 20, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
संकल्प

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

फा.सं. 6(1)/2011-केवीआई-II : केन्द्रीय सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (जिसे इसमें पश्चात् उक्त आयोग कहा गया है) की अधिसूचना का.आ. 1895(अ) को तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा विघटित कर दिया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 25 के उपधारा 2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार 24 जुलाई, 2014 की उक्त तारीख के ठीक पहले उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के अधीन सभी संपत्तियां और निधियां जो आयोग के अधिकार में थी, केन्द्रीय सरकार में निहित कर दी गई हैं;

और अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने आयोग के विघटित होने पर आयोग के सदस्यों अथवा अध्यक्ष के रूप में पद रिक्त कर दिया है;

और पूर्व आयोग की सभी सम्पत्तियां और निधियां, जो कि आयोग के विघटित होने के पश्चात् अब केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होना अपेक्षित है;

और विघटित होने से पूर्व आयोग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी विद्यमान नीतियां, कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप को समान निवन्धनों और शर्तों पर जारी रखना आवश्यक है।

अब, केन्द्रीय सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के नाम से एक प्राधिकार का गठन किया जाए जो कि उक्त आयोग की सभी सम्पत्तियों और निधियों की देखभाल करेगा, जो इसके विघटित होने के समय इसके अधिकार में थी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिन्हें इससे पूर्व उक्त आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (1956 का 61), खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा अनुपालन किया जा रहा था;

2. केन्द्रीय सरकार यह और संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, संगठन के समुचित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा तथा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगा अर्थात्:-

- i. संगठन के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा;
- ii. खादी और ग्रामोद्योग के स्थापन और विकास की योजना, संवर्धन, संगठन और सहायता में ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों के साथ, जहां आवश्यक हो, समन्वय करना;
- iii. खादी और ग्रामोद्योग में नियोजित या रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसका आयोजन करना;
- iv. कच्ची सामग्री और उपकरणों का आरक्षित निर्मित करना तथा उन्हें ऐसी दरों जो विनिश्चित की जाए, ऐसे व्यक्तियों को आपूर्ति करना जो कि हस्तनिर्मित रेशे या खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में लगे या लगने की संभावना है;

v. कच्ची सामग्रियों या अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना तथा खादी या ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन को अन्यथा सुविधा प्रदान करना;

vi. खादी की बिक्री एवं विपणन और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री और विपणन का संवर्धन;

vii. खादी और ग्रामोद्योगों में उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना तथा प्रोन्त करना, जिसके अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने, नीरसता कम करने की दृष्टि से, अ-पारंपरिक ऊर्जा और विद्युत शक्ति का उपयोग तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना और ऐसे अनुसंधान से प्राप्त विशेष परिणामों के प्रसार की व्यवस्था करना भी है;

viii. खादी और ग्रामोद्योगों की समस्याओं का सीधे अथवा किसी अन्य अभिकरण से अध्ययन करना;

ix. खादी और ग्रामोद्योग के विकास और प्रचालन से जुड़ी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें उत्पादन एवं सेवाओं के प्रयोजन के लिए डिजाइन, प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी देते करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करना;

x. प्रयोगिक अथवा आर्थिक परियोजना संचालित करना, जो खादी और ग्रामोद्योग उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हो;

xi. उपर्युक्त किसी अथवा सभी मामले को संचालित करने के लिए पृथक संगठन को रखना है;

xii. विशुद्धता सुनिश्चित करना और क्यालिटी के मानक स्थापित करना जिससे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों में उक्त मानक की पुष्टि हो सके, इसके अंतर्गत मैं संवर्धित व्यक्तियों को मान्यता के लिए प्रमाणपत्र अथवा पत्र जारी करना भी है;

xiii. केन्द्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता, खादी सुधार और विकास कार्यक्रम आदि और पूर्व आयोग द्वारा वैसी ही स्कीमों को कार्यान्वित करना;

xiv. प्रत्येक वर्ष में इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख अनुसार बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना;

xv. संगठन का प्राप्तियों और व्यय का लेखों को रखना और उनका अनुरक्षण करना;

xvi. व्यापारिक और अन्य क्रियाकलापों के लिए स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा किसी अधिकारी को अधिकारी संविदा करने के लिए प्राधिकृत करना परन्तु स्वीकृत बजट में इसका उपबंध किया विद्यमान हो;

xvii. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर खादी और ग्रामोद्योग के लिए बनाए गए ऋण नियमों उपबंधों के अनुसार और समय-समय पर एवं प्रत्येक उद्योग के संबंध में सरकार द्वारा मंजूर दरों और निबन्धन के अनुसार ऋण प्रदान करना;

xviii. केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के अनुसार, खादी, ग्रामोद्योग नियम की प्रतिभूति पर अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अन्य आस्तियों पर, उसी प्रयोजन के लिए उधार लेना उक्त नियम का अनुप्रयुक्त करना;

xix. निम्नलिखित किसी या सभी प्रवर्गों के अधीन आने वाली 10,000 रु. तक की राशि वित्तीय सलाहकार के पूर्व परामर्श से बट्टे खाते में डालना, अर्थात्:-

(क) हानि अथवा अवसूलीय मूल्य अथवा लोक धन की चोरी, कपट आदि होने की स्थिति में;

(ख) ऋण से भिन्न हानि एवं अवसूलीय अग्रिम; और

(ग) भण्डार के मूल्य में कमी और अवक्षयण।

xx. हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करना और हानि के लिए उत्तरदायी यदि कोई हो व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजना;

xxi. किसी करार, अभिव्यक्त अथवा विवक्षित अथवा अन्यथा जैसा भी हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में, खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त का संदेय रकम की वसूली करना;

xxii. किसी अन्य स्कीम अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाए;

xxiii. ऐसी अन्य कर्तव्यों को करना एवं ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समनुदेशित की जाए;

xxiv. केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पद्धति के निदेश जारी करना;

xxv. उपरोक्त के अतिरिक्त, कोई अन्य आनुषंगिक कार्य करना।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि पूर्व आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं सभी अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिसके अंतर्गत व्यापारिक संवर्ग भी हैं, पद पर बने रहेंगे तथा सेवा के मामले में उनकी प्रारिष्ठति वही होगी जो आयोग को विघटन के समय थी तथा अब से वे खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त के पर्यवेक्षण और समग्र नियंत्रण में कृत्य करेंगे।

4. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन से, इसके प्रभावी कृत्यों के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे तथा खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, उक्त आयोग के विघटन होने की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू विद्यमान नियमों के अनुसार प्रोन्ति, ऋण और अग्रिमों, छुट्टी, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आचरण के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

5. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 2003 में यथा उपर्युक्त अनुशासनिक प्राधिकारी के साथ-साथ नियुक्त प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी संकल्प करती है कि इस संबंध के लागू होने से पहले किसी भी समय खादी और ग्रामोद्योग के विकास के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा या उल्लिखित की गई सभी संविदाएं और विकास तथा बातें लागू होने के पश्चात् खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त के द्वारा उद्भूत या उसके द्वारा किया गया या उसके द्वारा किया गया समझा जाएगा।

7. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त में विधि के द्वारा संसद द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त को उपयुक्त कृत्यों के अनुपालन के लिए ऐसी रकम जो वह आवश्यक समझे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले संदाय करेंगी।

8. केन्द्रीय सरकार और यह संकल्प करती है कि:-

- (i) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त, खादी के विकास, ग्रामोद्योग के विकास अथवा खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति से उपहार, अनुदान, दान अथवा लाभ प्राप्त कर सकेंगा।
- (ii) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त तीन प्रथक निधियां, जो खादी निधि, ग्रामोद्योग निधि और साधारण और विविध निधि के नाम से जानी जाती है, को जारी रखेंगे तथा आयुक्त के पक्ष में प्राप्त सभी राशि को इन निधियों के नामे करेंगे और इसका उपयोजन उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जैसा कि आयोग के भंग किये जाने से ठीक पहले किया जाता रहा था।
- (iii) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपर्युक्त कृत्यों जिसके अनुपालन के लिए, विद्यमान समितियों और उपसमितियों को भी आवश्यक समझे, पुनर्गठित कर सकेंगा और नई समितियों और उपसमितियों का गठन कर सकेंगा।

9. खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त का मुख्यालय मुंबई होगा या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्देश दे।

10. खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त किसी कारण से कार्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से किसी अधिकारी को खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के दायित्वों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगी।

11. पूर्ववर्ती उपर्युक्तों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त जब इस संकल्प के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इसको दी जाने वाली ऐसी सलाह और निर्देश बाध्यकारी होंगे।

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
RESOLUTION

New Delhi, the 8th August, 2014

F.No.6(1)/2011-KVI-II.—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 25 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) has dissolved the Khadi and Village Industries Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) vide notification S.O. 1895(E), dated the 24th July, 2014, with effect from the 24th July, 2014;

And whereas in accordance with the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the said Act on and from the said date of the 24th July, 2014, all properties and funds which, immediately before the said date, were in the possession of the Commission for the purposes of the said Act have been vested in the Central Government;

And whereas all members including Chairman have vacated their office as members or Chairman of the Commission on dissolution of the Commission;

And whereas all properties and funds of the erstwhile Commission which have now got vested in the Central Government after the dissolution of the Commission are required to be administered by the Central Government through its designated authority;

And whereas, it has become necessary to continue all existing policies, programmes, schemes and all other related activities on the same terms and conditions as were being implemented by the erstwhile Commission immediately before its dissolution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under article 73 of the Constitution of India, the Central Government hereby resolves that an authority in the name of the Commissioner for Khadi and Village Industries be established who shall henceforth look after all the properties and funds of the said Commission, which were in its possession at the time of its dissolution and exercise all powers and perform functions of the Khadi and Village Industries Commission, which were hitherto being performed by the said Commission, under various provisions of Khadi and Village Industries Act, 1956 (61 of 1956), Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 and regulations made thereunder.

2. The Central Government further resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be responsible for the proper functioning of the organization and shall perform the following functions, namely :-

- (i) to exercise administrative control over all departments and officers of the organization;
- (ii) to plan, promote, organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary;
- (iii) to plan and organize training of persons employed or desirous of seeking employment in khadi and village industries;
- (iv) to build up reserves of raw materials and implements and supply them to persons engaged or likely to be engaged in production of handspun yarn or khadi or village industries at such rates as may be decided;
- (v) to encourage and assist in the creation of common service facilities for the processing of raw materials or semi-finished goods and for otherwise facilitating production and marketing of khadi or products of village industries;
- (vi) to promote the sale and marketing of khadi, and products of village industries;
- (vii) to encourage and promote research in the technology used in khadi and village industries, including the use of non-conventional energy and electric power with a view to increasing productivity, eliminating drudgery and otherwise enhancing their competitive capacity and to arrange for dissemination of salient results obtained from such research;
- (viii) to undertake directly or through other agencies studies of the problems of khadi or village industries;
- (ix) to provide financial assistance to institutions or persons engaged in the development and operation of khadi or village industries and guide them through supply of designs, prototypes and other technical information for the purpose of producing goods and services;
- (x) to undertake experiments or pilot projects which may be necessary for the development of khadi and village industries;
- (xi) to maintain separate organizations for the purpose of carrying out any or all of the above matters;
- (xii) to ensure genuineness and to set up standards of quality so that products of khadi and village industries conform to the said standards, including issue of certificates or letters of recognition to the concerned persons;
- (xiii) to implement the various schemes of the Central Government like the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Market Development Assistance (MDA), Khadi Reform and Development Programme (KRDGP), and like such Schemes being implemented by the erstwhile Commission;
- (xiv) to prepare and submit budget by such date in each year to the Central Government for approval as may be specified for this purpose;
- (xv) to maintain or cause to be maintained an account of the receipt and expenditure of the organization;
- (xvi) to enter into contracts, himself or through any officer authorised by him in connection with its trading and other activities provided provision therefor exists in the sanctioned budget;
- (xvii) to grant loans in accordance with the provisions of the loan rules for khadi and village Industries made by the Central Government from time to time, and in accordance with and at rates and on terms sanctioned by the Government in respect of each industry from time to time;
- (xviii) to borrow, with the previous sanction of the Central Government, on the security of the khadi fund, village industries fund or any other assets for any purposes for which such funds may be applied;
- (xix) to write off losses with the prior consultation with the Financial Adviser, upto 10,000 rupees falling under any or all of the following categories, namely:-
 - (a) loss or irrecoverable value of stores or of public money due to theft, fraud etc.;
 - (b) loss or irrecoverable advance other than loans; and
 - (c) deficiency and depreciation in the value of stores.
- (xx) to take suitable action against the persons responsible for the loss and shall also send to the Government a detailed report together with the action taken against the persons, if any, responsible for the loss;
- (xxi) to recover sum payable to the Commissioner for Khadi and Village Industries under any agreement, expressed or implied, or otherwise howsoever, in the manner as an arrear of land-revenue;
- (xxii) to implement any other scheme or perform such other functions which may be assigned to him by the Central Government;
- (xxiii) to undertake such other duties and exercise such other powers as may be assigned to him by the Central Government;
- (xxiv) to issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Central Government; and
- (xxv) to carry out any other functions incidental to the above.

3. The Central Government also resolves that the Chief Executive Officer, the Financial Adviser and all other employees of the erstwhile Commission, including those in the trading cadre shall continue to hold office and shall enjoy the same status in regard to service matters as they were doing at the time of dissolution of the Commission and shall henceforth function under the overall supervision and control of the Commissioner for Khadi and Village Industries.

4. The Central Government also resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries may appoint such other officers and staff, as it considers necessary for its efficient functioning with the prior approval of the Central Government and the Commissioner for Khadi and Village Industries shall also exercise all powers in the matters of promotion, loans and advances, leave, conduct of its officers and staff as per the existing rules applicable to Khadi and Village Industries Commission Employees on the date of dissolution of the said Commission.

5. The Central Government also resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries may exercise the powers of appointing authority as well as disciplinary authority as provided in the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003.

6. The Central Government also resolves that all liabilities incurred by, all contracts entered into with and all matters and things engaged to be done by or for the Khadi and Village Industries Commission in connection with the development of khadi or village industries at any time before the commencement of this Resolution, shall, after such commencement, be deemed to have been incurred by, entered into with, or engaged to be done by, or for, the Commissioner for Khadi and Village Industries.

7. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commissioner for Khadi and Village Industries in each financial year such sums as may be considered necessary for performing the aforesaid functions.

8. The Central Government further resolves that -

(i) The Commissioner for Khadi and Village Industries may for the purpose of development of khadi, the development of village industries or the development of khadi and village industries, receive gifts, grants, donations, or benefactions from the Government or any other person;

(ii) The Commissioner for Khadi and Village Industries shall continue to have three separate funds called the khadi fund, village industries fund and the general and miscellaneous fund and all sums received by the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be credited to these funds and shall also be applied for the purposes in the same manner as was being done immediately before the dissolution of the said Commission;

(iii) The Commissioner for Khadi and Village Industries may reconstitute the existing Committee(s) and sub-committee(s) and may constitute any new Committee(s) and sub-committee(s), as considered necessary, for performing any of the aforesaid functions, with the prior approval of the Central Government;

9. The headquarters of the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be at Mumbai or at such other place as the Central Government may from time to time direct;

10. The Commissioner for Khadi and Village Industries, if for any reason is unable to attend his office, any officer as may be specifically authorized by the Central Government shall discharge the duties and functions of the Commissioner for Khadi and Village Industries;

11. Without prejudice to the foregoing provision, while in discharge of its powers and functions under this resolution, the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be bound by such advice and directions as the Central Government may give to it from time to time.

B.H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.